



14 मिनट	8	24	1	GS1 • 2	GS2 • 17	GS3 • 17
पढ़ने का समय	मुख्य खबरें	संक्षेप में	मेन्स प्रश्न	पेपर मिश्रण		

01 — आज 2 मिनट में

5 खबरें जो छोड़नी नहीं हैं

1 राष्ट्रपति Droupadi Murmu ने केरल का नाम Keralam करने वाले बिल को मंजूरी दी

क्यों ज़रूरी: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिसके द्वारा केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम कर दिया गया है।

GS2 • राजव्यवस्था एवं संविधान

P

M

2 Saudi Arabia, Turkey और Pakistan ने किया डिफेंस समझौता, US ने दी तारीफ

क्यों ज़रूरी: सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने सामूहिक रक्षा प्रतिबद्धता को औपचारिक रूप देने के लिए 'मक्का संयुक्त रक्षा समझौता' (Mecca Joint Defence Agreement) पर हस्ताक्षर किए हैं, जो क्षेत्रीय सुरक्षा की गतिशीलता को प्रभावित करेगा।

GS2 • अंतर्राष्ट्रीय संबंध

P

M

3 कोइजुमी ने डिफेंस ties बढ़ाने और UNICORN ड्रोन के जॉइंट डेवलपमेंट पर चर्चा के लिए सिंह से मुलाकात की

क्यों ज़रूरी: जापानी रक्षा मंत्री शिनजीरो कोइजुमी रक्षा सहयोग के विस्तार, विशेष रूप से 'Make in India' ढांचे के अंतर्गत UNICORN प्रणालियों और ड्रोनों के संयुक्त विकास पर चर्चा करने के लिए भारत के दौरे पर हैं।

GS2 • अंतर्राष्ट्रीय संबंध

P

M

4 BRICS समिट से पहले अरुणाचल प्रदेश में चीन की घुसपैठ से भारत-चीन संबंधों पर खतरा

क्यों ज़रूरी: अरुणाचल प्रदेश में कथित चीनी अतिक्रमण ने भारत और चीन के बीच तनाव को बढ़ा दिया है, जिससे आगामी BRICS शिखर सम्मेलन प्रभावित होने की संभावना है।

GS2 • अंतर्राष्ट्रीय संबंध

P

M

5 उच्चतम न्यायालय ने परमाणु दुर्घटना मुआवजे पर प्रस्तावित सीमा की संवैधानिकता और परमाणु ऊर्जा नियामक निकाय (AERB) में हितों के संभावित टकराव पर प्रश्न उठाए हैं

क्यों ज़रूरी: उच्चतम न्यायालय ने परमाणु दुर्घटना मुआवजे पर प्रस्तावित सीमा की संवैधानिकता और परमाणु ऊर्जा नियामक निकाय (AERB) में हितों के संभावित टकराव पर प्रश्न उठाए हैं।

GS2 • राजव्यवस्था एवं संविधान

P

M

GS2 · राजव्यवस्था एवं संविधान

P

M

राष्ट्रपति Droupadi Murmu ने केरल का नाम Keralam करने वाले बिल को मंजूरी दी

चर्चा में क्यों: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिसके द्वारा केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम कर दिया गया है।

याद रखें

- संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को किसी भी राज्य के नाम, सीमाओं या क्षेत्रों को बदलने की शक्ति प्रदान करता है।
- संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम शामिल हैं।
- The Kerala (Alteration of Name) Bill, 2026, नाम परिवर्तन के लिए विधायी वाहन था।

मेन्स कोण भारत में राज्यों के नाम और सीमाओं के परिवर्तन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों और इसके संघीय निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/news/106574

GS2 · अंतर्राष्ट्रीय संबंध

P

M

कोइजुमी ने डिफेंस ties बढ़ाने और UNICORN ड्रोन के जॉइंट डेवलपमेंट पर चर्चा के लिए सिंह से मुलाकात की

चर्चा में क्यों: जापानी रक्षा मंत्री शिनजीरो कोइजुमी रक्षा सहयोग के विस्तार, विशेष रूप से 'Make in India' ढांचे के अंतर्गत UNICORN प्रणालियों और ड्रोनों के संयुक्त विकास पर चर्चा करने के लिए भारत के दौरे पर हैं।

याद रखें

- शिनजीरो कोइजुमी: जापान के रक्षा मंत्री।
- UNICORN: गुप्त संचार (stealth communication) के लिए एक नौसेना रेडियो एंटीना प्रणाली।
- भारत-जापान रक्षा नीति संवाद: 13 जुलाई, 2026 को टोक्यो में आयोजित।

मेन्स कोण एक मुक्त और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में भारत-जापान रक्षा सहयोग के महत्व पर चर्चा कीजिए। प्रौद्योगिकी साझाकरण द्विपक्षीय रणनीतिक स्वायत्तता को किस प्रकार सुदृढ़ करता है? विश्लेषण कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/news/106690

GS2 · अंतर्राष्ट्रीय संबंध

P

M

Saudi Arabia, Turkey और Pakistan ने किया डिफेंस समझौता, US ने दी तारीफ

चर्चा में क्यों: सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने सामूहिक रक्षा प्रतिबद्धता को औपचारिक रूप देने के लिए 'मक्का संयुक्त रक्षा समझौता' (Mecca Joint Defence Agreement) पर हस्ताक्षर किए हैं, जो क्षेत्रीय सुरक्षा की गतिशीलता को प्रभावित करेगा।

याद रखें

- Mecca Joint Defence Agreement पर 7 अगस्त को जेद्दाह में हस्ताक्षर किए गए।
- यह समझौता NATO के Article 5 पर आधारित है, जो सामूहिक रक्षा (collective defence) को अनिवार्य बनाता है।
- जेद्दा वह स्थान है जहाँ इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

मेन्स कोण मध्य पूर्व की भू-राजनीतिक स्थिरता और दक्षिण एशिया की सुरक्षा संरचना पर 'मक्का संयुक्त रक्षा समझौते' के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/news/106211

GS2 · अंतर्राष्ट्रीय संबंध

P

M

BRICS समिट से पहले अरुणाचल प्रदेश में चीन की घुसपैठ से भारत-चीन संबंधों पर खतरा

चर्चा में क्यों: अरुणाचल प्रदेश में कथित चीनी अतिक्रमण ने भारत और चीन के बीच तनाव को बढ़ा दिया है, जिससे आगामी BRICS शिखर सम्मेलन प्रभावित होने की संभावना है।

याद रखें

- अरुणाचल प्रदेश: पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य जो चीन, भूटान और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है।
- BRICS: ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका से मिलकर बना एक अंतर-सरकारी संगठन।
- यह सीमा विवाद भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) से संबंधित है।

मेन्स कोण भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और ब्रिक्स (BRICS) ढांचे के भीतर बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने की उसकी क्षमता पर सीमा विवादों के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/news/106518

उच्चतम न्यायालय ने परमाणु दुर्घटना मुआवजे पर प्रस्तावित सीमा की संवैधानिकता और परमाणु ऊर्जा नियामक निकाय (AERB) में हितों के संभावित टकराव पर प्रश्न उठाए हैं

चर्चा में क्यों: उच्चतम न्यायालय ने परमाणु दुर्घटना मुआवजे पर प्रस्तावित सीमा की संवैधानिकता और परमाणु ऊर्जा नियामक निकाय (AERB) में हितों के संभावित टकराव पर प्रश्न उठाए हैं।

याद रखें

- AERB: Atomic Energy Regulatory Body भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सुरक्षा और विकिरण संरक्षण को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार एक वैधानिक निकाय है।
- SHANTI Act के तहत प्रस्तावित देयता सीमा (liability cap) ₹3,000 करोड़ है।
- परमाणु दुर्घटना मुआवजे से संबंधित याचिका पर सुनवाई करने वाली पीठ की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने की।

मेन्स कोण भारत में परमाणु सुरक्षा नियमों के संदर्भ में, औद्योगिक दायित्व सीमाओं (industrial liability caps) और मौलिक अधिकारों के संरक्षण के बीच संतुलन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/news/106441

समुद्री निगरानी के लिए भारत ने 2 MQ-9B ड्रोन के लिए Rs 1,943 करोड़ का सौदा किया

चर्चा में क्यों: भारत ने समुद्री निगरानी और हवाई रक्षा को सुदृढ़ करने हेतु General Atomics के साथ दो MQ-9B SeaGuardian ड्रोनों के लिए 1,943 करोड़ रुपये का पट्टा समझौता (lease agreement) किया है।

याद रखें

- MQ-9B SeaGuardian: एक समुद्री निगरानी ड्रोन जो लंबी दूरी के संचालन में सक्षम है।
- अनुबंध मूल्य: 30 महीने की पट्टा अवधि के लिए Rs 1,943 करोड़।
- परिचालन क्षमता: 40,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर 30 घंटे से अधिक की उड़ान अवधि।

मेन्स कोण भारतीय महासागर क्षेत्र में 'सागर' (SAGAR) पहल और भारत की समुद्री सुरक्षा में MQ-9B सी-गार्डियन जैसे मानवरहित हवाई वाहनों (UAVs) के एकीकरण के योगदान का विश्लेषण कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/news/106384

वोटर नोटिस की डेडलाइन: 93 लाख तेलंगाना वोटरर्स को जल्द करना होगा एक्शन

चर्चा में क्यों: तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 93 लाख मतदाताओं के मतदाता सूची में नाम संबंधी विसंगतियों और त्रुटियों को सुधारने हेतु विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की घोषणा की है।

याद रखें

- मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) निर्वाचन नामा की तैयारी और रखरखाव के लिए जिम्मेदार राज्य-स्तरीय प्राधिकरण है।
- वर्तमान संशोधन में तेलंगाना के लगभग 93 लाख मतदाता नाम के मिलान में विसंगति से प्रभावित हैं।
- Special Intensive Revision (SIR) दस्तावेजों के सत्यापन के माध्यम से मतदाता सूची की अखंडता सुनिश्चित करने की एक प्रक्रिया है।

मेन्स कोण भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने में सटीक मतदाता सूची बनाए रखने के महत्व पर चर्चा कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/news/106744

सुप्रीम कोर्ट: फसल नुकसान के बावजूद हाथी गलियारों की रक्षा करें, कोई रुकावट न हो

चर्चा में क्यों: उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को हाथी गलियारों में आने वाली बाधाओं का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है, जिसमें फसल के नुकसान की तुलना में वन्यजीवों के आवागमन को प्राथमिकता दी गई है।

याद रखें

- MoEFCC: Ministry of Environment, Forest and Climate Change वन्यजीव संरक्षण के लिए नोडल निकाय है।
- हाथी गलियारे (Elephant corridors): खंडित आवासों के बीच आवाजाही के लिए हाथियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले निर्दिष्ट मार्ग।
- न्यायालय ने हाथियों के विरुद्ध हथियारों या दंडात्मक कार्रवाई के उपयोग को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया।

मेन्स कोण भारत के खंडित पारिस्थितिक तंत्रों में प्रवासी गलियारों के संरक्षण और मानव-वन्यजीव संघर्ष के बीच संतुलन स्थापित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/news/106395

GS1 · इतिहास · समाज · भूगोल

विशाखापट्टनम एयरपोर्ट से कमर्शियल फ्लाइट्स बंद, VTZ कोड अब भोगारामपुर जाएगा

असम सरकार ने उन सरकारी कर्मचारियों से उनके वेतन में से 20% तक की कटौती करने की नीति की घोषणा की है, जो अपनी पहली पत्नी से तलाक लिए बिना पुनर्विवाह करते हैं

GS2 · राजव्यवस्था · शासन · सामाजिक न्याय · अंतर्राष्ट्रीय संबंध

राष्ट्रपति Paudel ने Indian Army Chief Seth को जनरल की मानद पदवी दी
कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक को SC की क्लास

झारखंड CM ने 2014 से अब तक के भर्ती एंजाम रद्द किए, जांच कमेटी गठित
आंध्र प्रदेश ने टाइटल ट्रांसफर पर यूनिफॉर्म म्यूटेशन फीस के लिए बिल पास किया

तालिबान ने सत्ता में 5 साल पूरे किए, महिलाओं के अधिकारों पर रोक के लिए आलोचना का सामना

तमिलनाडु CM ने हाउसिंग प्लॉट्स के लिए 'Presence-less Registration' लॉन्च किया, 24 घंटे में ऑनलाइन वेरिफिकेशन

रिपोर्ट: एशियाई और प्रशांत द्वीपवासियों में भारतीयों को ICE ने सबसे ज्यादा टारगेट किया

केरल ने यौन अपराधों के 300 बच्चे पीड़ितों के लिए ₹12 लाख आवंटित किए

DRI ने ₹2,500 करोड़ का अरचिनट फ्रॉड नेटवर्क पकड़ा, 9 गिरफ्तार

सुप्रीम कोर्ट ने NGO की सिविक इलेक्टोरल रोल बेस ईयर 2002 बदलने की मांग खारिज की

GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा

अमित शाह ने Independence Day से पहले ISI समर्थित आतंकी raids में 253 की गिरफ्तारी की घोषणा की

AI-पावर्ड संस्कृत लेसन: EMRC को 440 डिजिटल कोर्स के लिए ₹70 लाख का प्रोजेक्ट मिला

CSIR-IICT और Re Sustainability ने चक्रीय अर्थव्यवस्था (circular economy) को बढ़ावा देने के

केरल के मुख्यमंत्री ने मूल्यवर्धित कृषि उत्पादों के निर्यात को सुगम बनाने के लिए 'केरल ब्रांड' पहल की घोषणा की और एक नई कृषि नीति की रूपरेखा प्रस्तुत की

केरल का नया नियम: लोकल लोन न चुकाने पर विभाग की जांच और फंड में कटौती

IMD Red Alert: बाढ़ से प्रभावित 5 लाख लोगों में से 2.37 लाख को ओडिशा में निकाला गया

पुरानी कारों के लिए EIO पेट्रोल का प्रस्ताव ताकि E20 से 6-7% एनर्जी पेनल्टी से बचा जा सके

JetZero का Z4 'manta ray' विमान 30-50% कम ईंधन में 5,750-मील की उड़ान का लक्ष्य

असम CM ने बाढ़ प्रभावित 96,842 परिवारों को ₹15,000 दिए

El Niño से उत्पादन पर खतरा, भारत घटा सकता है चीनी एक्सपोर्ट

भारत ने रिफाइनर्स को LPG उत्पादन बढ़ाकर रोजाना 63,810 टन करने का आदेश दिया

WhatsApp पर PAN, Aadhaar शेयर करने से पहचान चोरी का खतरा; RBI ने 2024-25 में दर्ज किए 23,953 फ्रॉड केस

GS2 • राजव्यवस्था एवं संविधान

भारत में राज्यों के नाम और सीमाओं के परिवर्तन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों और इसके संघीय निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।



टेलीग्राम



वेबसाइट

हर सुबह **टेलीग्राम** पर पाएँ

रोज़ सुबह 5 बजे पीडीएफ + क्विज़ • हर रविवार साप्ताहिक • हिंदी और अंग्रेज़ी • मुफ्त, बिना साइन-अप।

t.me/satyadheesh • satyadheesh.in/upsc/reports

नोट्स सत्याधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से बनाए जाते हैं और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़े हैं। उत्तर में उपयोग से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।